'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

प्रकाशन तिथि– 15 जनवरी, 2013

DL(ND)-11/6144/2013-14-15

R.N.I. No. 68180/98

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 16 ● अंक 4 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 जनवरी, 2013

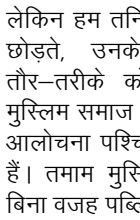

जहां मन हिंसा से मुड़ता है, वहां दुःख अवश्य ही शांत हो जाता है।

-गौतम बुद्ध

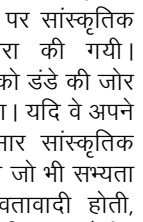

भारत बनाम इंडिया

डॉ. उदित राज

आर.एस.एस. के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बलात्कार एवं महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव पर बयान दिया कि यह सबकुछ पश्चिमी सभ्यता के कारण हो रहा है। विहिप के नेता अशोक सिंघल सहित आशाराम बापू आदि ने ऐसा ही बयान दिया। बयान देने से पहले इन्हें सोचना तो चाहिए कि हमारी सभ्यता में कुछ न कुछ खामी जरूर है, तभी तो हमारे लोग दूसरी सभ्यता से प्रभावित हो जाते हैं। यूरोप एवं अमेरिका का समाज तो नहीं कोसता कि उनके लोग हिन्दू सभ्यता से बिगड़ रहे हैं, जबकि ऐसी संभावना पूरी–पूरी है, क्योंकि हमारे लोग बड़ी संख्या में इन देशों में रहते हैं। अमेरिका एवं यूरोप के लोग बहुत कम संख्या में भारत में हैं और वे व्यापार या सरकारी जिम्मेदारी पूरा होते ही अपने देश वापिस लौट जाते हैं न कि यहां पर रच और बस जाएं। बेहतर होता कि ये लोग अपनी सभ्यता की खामियों को स्वीकार करते हुए दूर करते।

हमारी सभ्यता का आधार जातीय व्यवस्था है और इस व्यवस्था के शिकार जितना दलित, आदिवासी एवं पिछड़े हैं, उतना ही महिलाएं। हजारों वर्षों से सवर्ण समाज इस व्यवस्था को सर्वोत्तम कहते थकता नहीं और दूसरों को कमतर। यूरोप एवं अमेरिका के लोग शायद ही भारतीय सभ्यता को बुरा कहते हैं, लेकिन हम तनिक सा भी मौका नहीं छोड़ते, उनके रहन–सहन और तौर–तरीके को गलत बताने में। मुस्लिम समाज के लोग तो ज्यादा ही आलोचना पश्चिमी सभ्यता की करते हैं। तमाम मुस्लिम नेताओं के द्वारा बिना वजह पब्लिक सभाओं से पश्चिम सभ्यता पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि वहां पर औरतें अर्द्धनग्न रहती हैं, तलाक और गर्भपात भारी पैमाने पर होता है। पश्चिम के तमाम देशों को देखने और समझने का मौका मिला लेकिन कभी नहीं देखा हिन्दू और मुस्लिम सभ्यता की आलोचना करते हुए।

हमारे दो प्रमुख महाकाव्य हैं – एक है गीता एवं दूसरा रामचरित्मानस। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लड़ाई रावण से सीता को लेकर हुई। सीता को पहले लक्ष्मण रेखा पार न करने के लिए कहा गया था लेकिन वे गलती कर गयीं और रावण उन्हें उठा ले गया। यह प्रकरण भी औरत को कमतर दिखाता है। इन दोनो में युद्ध होता है और रावण के हारने के बाद सीता पुनः वापिस आती हैं तो उनकी अग्नि परीक्षा ली जाती है कि कहीं उन्होंने अपनी इज्जत तो नहीं गंवा दिया। पुरुष को अग्निपरीक्षा देने की जरूरत है ही नहीं, जैसे कि उसकी इज्जत हो ही न। यहां स्पष्ट हो जाता है कि औरत एक वस्तु है, भोग्या है और उसका दर्जा पुरुष से कम है। बात यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि तब स्थिति और दर्दनाक बन जाती है जब पड़ोसी के कहने पर राम सीता को घर से निकाल देते हैं। राम को सीता के चरित्र पर शक हुआ तभी तो उन्होंने घर निकाला किया। सीता का इतना भी अधिकार नहीं होता है कि उनको रहने के लिए व्यवस्था कर दी जाए बल्कि जंगल में छोड़वा दिया जाता है। आज का कानून ऐसा करने की

इजाजत नहीं देता है और जब संबंध विच्छेद की स्थिति आती भी है तो महिला को जीवन–यापन के लिए पुरुष को सहायता देनी पड़ती है। जब हमारी यही सभ्यता है तो महिलाएं पश्चिम सभ्यता से प्रभावित तो होंगी ही क्योंकि वहां पर आजादी, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता ज्यादा है। यहीं पर अपने गिरेबान में झांककर देखने की बहुत ही जरूरत है कि उन सड़ी–गली परंपराओं व मान्यताओं को दफन किया जाए, जिससे महिलाएं कमतर मानी जाती हैं, बजाय कि दोष किसी और पर डाल देना। अतीत में पश्चिम के देशों में भी भेदभाव रहे हैं, लेकिन उन्होंने तेजी से उन्हें दूर करने की भी कवायद की। ग्रीक की सभ्यता का विकास किस तरह से आगे बढ़ता है, उसे समझना जरूरी है। सुकरात ने जो दर्शन दिये उनके शिष्य प्लेटो ने उतना ही माना जितना उनको मानव के हित में या तर्कसंगत लगा। अर्थात् सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम किया। अरस्तू प्लेटो के सिद्धांतों व दर्शन से बहुत प्रभावित होते हुए भी उन्हीं बातों को माना जो उन्हें तर्कसंगत लगी। इस तरह से यथास्थितिवाद की जकड़न से समाज मुक्त होता रहा और आज जो पश्चिम की सभ्यता है, वह ऐसी ही परंपराओं एवं रीतिरिवाजों की बुनियाद पर बनी है। हमारे यहां चाहे जितनी अच्छी एवं प्रगतिशील बात हो लेकिन अंत में यह शायद कोई ही न कहता हो कि पुराने जमाने की बात ही क्या है? अर्थात् पुरानी परंपरा को ही सर्वोच्च माना जाता है। इस तरह से यहीं पर हम मार खाते हैं और पश्चिमी सभ्यता के सामने व्यावहारिकता में पीछे हो जाते हैं। दुनिया में हमसे ज्यादा मियां–मिट्ठू कोई समाज नहीं है, जो यह कहते हुए थकता नहीं कि जो हमारा धर्म, सोच और रहन–सहन है, उसका कोई मुकाबला है ही नहीं। आज जब महिलाएं संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार जीना चाहती हैं तो उन्हें बर्बस पश्चिम की सभ्यता से प्रभावित होना पड़ता है, क्योंकि वहां मानवाधिकार, समानता, आत्मनिर्भरता, आजादी ज्यादा है। समानता एवं सम्मान की भूख जब जग गयी है तो रहना–सहना भी बदलता है और वह पश्चिम सभ्यता के तमाम मूल्यों से अपने आप मेल खा जाता है। हमें अपने आपको परिवर्तित करने से पश्चिमी देशों के लोगों ने रोका नहीं। जो परिवर्तन वहां हुआ यदि उसे हम अपने परिवेश के अनुसार ढाल लेते तो आज पश्चिम सभ्यता से प्रभावित होने की जरूरत ही न होती और हो सकता है कि दूसरी सभ्यताओं को हम कुछ दे सकते। अभी भी रामचरितमानस के उस अंश की सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं की गयी जो यह कहता हो कि ढोल, गवांर, शूद्र, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका आशय है कि महिला मारने से ही काम करती है और वह पशु समान है। महाभारत के उस अंश की भी निंदा नहीं की गयी, जब पांडव जुआ खेलते–खेलते सबकुछ हार जाते हैं और दांव लगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं रह जाता तो द्रौपदी को लगा देते हैं और कौरव जीत जाते हैं। क्या आज कोई व्यक्ति अपनी औरत को जुआ में खेलने की हिम्मत कर सकता है? जिन्होंने स्वयं द्रौपदी को सम्मान नहीं दिया, उसे वस्तु माना और धर्मराज कहलाए जबकि कौरवों का दोष कम है, लेकिन चित्रित इस तरह से किया गया कि दुष्ट वहीं हैं, बल्कि कौरवों का पक्ष बेहतर है और अगर वे द्रौपदी का चीरहरण भी करते हैं तो जिम्मेदार कौन है?

पश्चिम के तमाम देशों में विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति हुई है, लेकिन हमारे यहां नहीं हो सकी। कबीर जैसे संतों ने कोशिश तो जरूर की लेकिन वह व्यावहारिक पटल पर नहीं पहुंच सका। ज्योतिबाफुले ने महिलाओं की आजादी और शिक्षा की मिसाल स्थापित करके शुरुआत तो की लेकिन समाज की जड़ता नहीं टूटी। अम्बेडकरवादी आंदोलन जरूर जातिवादी और मनुवादी व्यवस्था को चुनौती देता है, लेकिन अभी उसे बड़ी यात्रा करनी पड़ेगी। व्यक्ति को समानता, सम्मान, स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता आदि प्राप्त करने में जहां से भी सहयोग मिलता है, वहां से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। समय रहते हुए यदि हम सड़ी–गली परंपराओं को तोड़ते तो जीवन जीने के लिए ये आवश्यकताएं हम अपने यहां से ही पूरा कर लेते तो पश्चिम के देश से प्रभावित होने की जरूरत ही नहीं थी। चीन हमसे कम रूढ़िवादी नहीं था लेकिन वहां पर सांस्कृतिक क्रांति सत्ता के द्वारा की गयी। प्रतिक्रियावादी मूल्यों को डंडे की जोर से भी खत्म किया गया। यदि वे अपने यहां समय के अनुसार सांस्कृतिक क्रांति न किये होते तो जो भी सभ्यता प्रगतिशील एवं मानवतावादी होती, उनके समाज को प्रभावित कर देती। हमें आज़ादी प्राप्त किये 65 वर्ष हो गया और सरकारों ने तमाम योजनाएं बनायीं, लेकिन जाति तोड़ने एवं पुरुषवादी सोच को खत्म करने का प्रयास नहीं किया गया। यह कार्य समाज के कठमुल्लों पर छोड़ दिया गया। भला वे क्यों सामाजिक परिवर्तन करते? सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए था, लेकिन वोटबैंक खराब न हो, इसलिए अधिकतर नेता परिवर्तन करने के लिए आंदोलन किए ही नहीं। चाहे सामाजिक नेतृत्व हो या राजनैतिक, ज्यादातर लोग खुद ही रूढ़िवादी रहे और पुरानी भेदभाव एवं असमानता वाली सोच से ऊपर नहीं उठ सके।

शेष पृष्ठ 5 पर...

पटना में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ समागम जुटे 17 देशों और 17 राज्यों के बौद्ध

संजय कुमार

पटना। ढाई हजार साल पहले सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र की धरती पर तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। पाटलिपुत्र की धरती, बिहार के पटना स्थित बुद्ध स्मृति पार्क में (6 से 8 जनवरी 2013) तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ समागम में देश और विदेश से आये बौद्ध विद्वानों ने गहन विचार–विमर्श कर एक बार फिर इतिहास दोहराया। परम पावन बौद्ध गुरू दलाई लामा और 17 देशों और भारत के 17 राज्यों के के बौद्ध गुरूओं की मौजूदगी में पाटलिपुत्र का करूणा स्तूप परिसर बुद्धं शरणम् गच्छामि के जयघोष से गूंज उठा। दलाई लामा ने बौद्ध संघ समागम का दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया।

बौद्ध गुरू दलाई लामा ने कहा कि सबसे पहले भगवान बुद्ध, जिन्होंने करूणा का मार्ग दिखाया, उनके चरणों में नमन करते हुए, चाहे बौद्ध धर्म के अनुयायी हो या न हो, मात्र जिज्ञासा रखते हो, मुख्यमंत्री, बिहार व सभी वरिष्ठ लोगों एवं सभी भाई–बहनों को, जो इस धर्म समागम में आये हैं, यहां आमंत्रित करने लिए स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूं। मुख्यमंत्री ने जो यहां बौद्ध स्तूप स्थापित किया है, इसमें ध्यान–साधना की व्यवस्था की है, अध्ययन के लिए पुस्तकालय स्थापित करने की योजना है। इससे यह पता चलता है कि आपने शुरू, मध्य व अंत के लिए सभी तरह के विकास की दिशा में पहल की है। बिहार जो शब्द है, वह स्वयं में अर्थपूर्ण है, जिस तरह हम इक्कीसवीं सदी की शुरूआत में हैं, समय जो परिवर्तशील है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अतीत से हम सिर्फ अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। हमें अतीत के अनुभव की बुनियाद पर वर्तमान की कठिनाई को हल करने की ओर बढ़ना चाहिए।

दलाई लामा ने कहा कि, आज दुनिया में तकनीकी विकास हो रहा है। विज्ञान और तकनीक के माध्यम से कई समाज या देश विकासशील स्थिति में है। इसके साथ ही बिहार को देखें। दूसरी ओर ऐसे देश व समाज भी हैं, जहां अपार धन–दौलत है, समाज में विकास हुआ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। ऐसे में मानसिक विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। जब मानसिक विकास नहीं होगा, तो ईमानदारी, लाभ–हानि आदि की बात कैसे समझ सकते हैं? मन से संबंधित सुख–दुख, ईर्ष्या, मुकाबला पैदा होने का खतरा बना रहता है।

उन्होंने कहा कि, विश्व सेवा का संकल्प लेंने की आवश्यकता है। आज शोध हो रहा है। चिकित्सालय से संबंधित वैज्ञानिक हैं, मस्तिष्क व मन विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक हैं, शिक्षा से संबंधित हैं, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया में करूणा व मैत्री के अभाव के कारण कई कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। कुछ समय पहले जो आर्थिक कठिनाइयां पैदा हुई थी, वे लालच बढ़ने के कारण सामने आयीं। हमें प्रयास करना चाहिए, करूणा व मैत्री का विस्तार हो। भौतिक विकास के साथ मानसिक विकास हो। करूणा व मैत्री के विस्तार की दिशा में सभी धर्मो के संतों व संस्थाओं का प्रयास करना चाहिए। सभी की जिम्मेवारी है कि एकता बनाये रखे, संकल्प लें कि हम क्या कर सकते हैं, यहां जो भी बौद्ध भिक्षु पधारे हैं, संकल्प लें कि विश्व की कैसे सेवा कर सकते हैं।

वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में नया बौद्ध स्तूप बनाने की घोषणा की। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में वहां स्तूप बनवाया था, जिस पर सिंह की मूर्त्ति है। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघ समागम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सिर्फ ग्यारह करोड़ बिहारवासियों का नहीं, बल्कि दुनिया भर के बौद्ध धर्मवालंबियों की धरती है। मुख्यमंत्री ने ताइवान, कंबोडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल, हांगकांग, श्रीलंगा, जावा, म्यांमार और अन्य देशों से आये प्रतिनिधियों से बिहार की प्रगति के लिए सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री ने दलाई लामा को नमन करते हुए कहा, 2005 में नयी सरकार बनी। इसके बाद जब परम पावन बिहार आये, तो हमने आर्शीवाद देने का अनुरोध किया था। इस पर उन्होंने कहा था–जब बिहार को भगवान बुद्ध का आर्शीवाद मिला है, तो बिहार पीछे क्यों है? हमने उनके मर्म को समझा और सब लोगों ने साफ नीयत से काम किया। नतीजा बिहार आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध से संबंधित सभी जगहों को विरासत मान कर हम रक्षा करेंगे। जगहों की खुदाई की जायेगी। करूणा स्थल में छह जगहों से लायी गयी अस्थियों को रखा गया है। वैशाली में एक और स्तूप सरकार बनायेगी। इसमें पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखे अवशेष को स्थापित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार बौद्ध सर्किट को विकसित करेगा और पर्यटकों की सुविधा के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और कल भी प्रासंगिक रहेंगे। बिहार अद्भूत जगह है। यहां बुद्ध हुए। महावीर भी हुए सिख और अन्य धर्मों के लोग भी आये। यहां सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण है। इसकी तरक्की में आप सबका भी योगदान चाहिए। बिहार फिर से ज्ञान का केंद्र बनेगा।

अंतराष्ट्रीय बौद्ध संघ समागम के दूसरे दिन बौद्ध विद्वानों ने माना कि बिहार एक बार फिर से अपनी पुरानी कृति को पाने की राह पर चल पड़ा है। जापान के शांति सुगेई ने कहा कि बिहार आदिकाल से ही बौद्ध धर्म को स्थापित करने का केन्द्र रहा है। सम्राट अशोक ने बौद्ध दर्शन से प्रेरित होकर अहिंसा का मार्ग अपनाया और दुनिया भर में पचासी हजार स्तूप और मठ बनवाये थे। बिहार फिर से अशोक काल की कीर्ति को पाने की राह पर चल पड़ा है। शहर में बना बौद्ध स्मृति पार्क इसी कड़ी की शुरूआत है। बुद्ध के उपदेशों का संरक्षण और समृद्धि इसी तरह से किया जा सकता है। शांति सुगेई इस समागम में दूसरे सत्र के विषय बुद्ध के अपदेशों के संरक्षण और समृद्धि में बौद्ध संघ की भूमिका पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होनें अशोक कालीन इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला। कहा कि भारत को बौद्ध दर्शन की समृद्धि के लिए किए ऐसे प्रयासों के सिलसिला को बढ़ाने की आवश्यकता है। माहात्मा गांधी का आंदोलन अहिंसा का सबसे अच्छा उदाहरण है।

भारत में बुद्ध धर्म के संरक्षण की चुनौतियों और इसे भारतीय संदर्भ से जोड़कर त्रिपुरा के बौद्ध विद्वान डॉ. धर्मप्रिय ने व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि बुद्ध के उपदेशों के संरक्षण और संवर्द्धन की पहली जिम्मेवारी सभी बौद्ध संघों की है। भारत के सभी संघों में क्षमता, क्रियाशीलता और एकजुटता की कमी होने से उपदेशों का वे संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के करीब एक फीसदी बौद्ध समुदायों को तीन हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, हिमाचल क्षेत्रों (सिक्किम से हिमाचल प्रदेश तक) में रहने वाले, दूसरा पारंपरिक बौद्ध (असम, त्रिपुरा समेत अन्य पूर्वोत्तर राज्य) और तीसरा बी आर आम्बेडकर से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोग। तीनों का सामाजिक दर्शन और संस्कृति बिल्कुल अलग है। संवर्द्धन के लिए तीनों में एकजुटता की आवश्यकता है। धर्मप्रिय ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में ईसा समुदाय बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबियों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। यह एक बड़ी समस्या है। उन्होंने इस संदर्भ में त्रिपुरा के चकमा खानाबदोशों का उदाहरण देते हुए कहा कि कई पूर्वोत्तर राज्यों में यह समस्या है।

भारत के डॉ. वांगचूक दोरजे नेगी ने कहा कि बौद्ध धरोहर स्थलों का संरक्षण करने के लिए स्थानीय लोगों को बुद्ध धर्म की जानकारी देने की आवश्यकता है। जानकारी के अभाव में नालंदा के समीप एक गांव में बुद्ध की मूर्ति को तेलिया बाबा और वैशाली में एक प्रतिमा को पंचबुद्ध के रूप में स्थानीय लोगों ने पूजना शुरू कर दिया है। ऐसे में बौद्ध धर्म का प्रचार और लोगों को उचित जानकारी देना जरूरी है।

तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ समागम के समापन सत्र 7 जनवरी, को संबोधित करते हुए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की मंत्री सुखदा पांडे ने कहा कि बौद्ध विरासत के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए बिहार सरकार प्रयत्नशील है।

इस समागम में विश्व के विभिन्न देशों से आये बौद्ध विद्वानों ने 21वीं शताब्दी में बौद्ध संघों की भूमिका के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। इसके आधार पर समापन समारोह में एक संकल्प भी पारित किया गया। समागम के संयोजक टेनजी प्रियदर्शी रिनपोचे ने संकल्प पाठ करते हुए बताया कि इस प्रकार के समागम विभिन्न स्थलों पर नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पाटलिपुत्र करुणा स्तूप अंतरधार्मिक संवाद एवं समझ को बढ़ानेवाला केन्द्र होगा। विनय नियम के संरक्षण के लिए सभी परम्पराओं के संघ सदस्यों के बीच नियमित संवाद जारी रहना चाहिए तथा इस संबंध में सेमिनार आदि भी आयोजित किये जाने चाहिए।

संकल्प में युवा भारतीय मौंक एवं नन के लिए बौद्ध शिक्षण संस्थान की आवश्यकता बताते हुए कहा गया कि बौद्ध धर्म की जन्मस्थली होने के कारण बिहार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बौद्ध धर्म में महिलाओं की भूमिका के संबंध में वैशाली का विशेष महत्व बताते हुए नन के लिए शिक्षण हेतु विशेष प्रयास पर बल दिया गया। विभिन्न भाषाओं में बौद्ध साहित्यों के प्रकाशन एवं इनके प्रचार–प्रसार का उल्लेख भी संकल्प में किया गया।

संकल्प में कहा गया कि भारत, विशेषकर बिहार में, बौद्ध स्थलों की खुदाई हेतु और अधिक प्रयास किया जाना चाहिए तथा स्थानीय लोगों के मदद से इनका संरक्षण किया जाना चाहिए एवं लोगों को इनके बारे में जागरूक भी किया जाना चाहिए। विश्व के विभिन्न बौद्ध विहारों के सदस्यों को कम प्रसिद्ध स्थलों पर भ्रमण करना चाहिए। आध्यात्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया कि इसे ध्यान में रखते हुए ही बुद्धिस्ट सर्किट की स्थापना की जानी चाहिए।

इससे पूर्व भारत में बौद्ध विरासत से जुड़े स्थलों के पहचान एवं संरक्षण में बौद्ध संघों की भूमिका के विषय में भारत, हांगकांग एवं यूनाइटेड किंगडम के विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किये।

समापन समारोह को कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव चंचल कुमार ने भी संबोधित किया। स्वागत भाषण नव नालंदा महाविहार के निदेशक डॉ0 आर0 पंथ एव धन्यवाद ज्ञापन बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के सचिव एन0 दोरजी ने किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष–सह–गया की जिलाधिकारी वंदना प्रेयसी ने विभिन्न महानुभावों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

28 फरवरी को लखनऊ में दलित-पिछड़ा-अल्पसंख्यक सम्मेलन

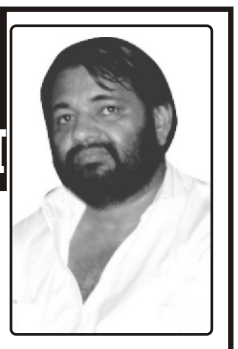

28 फरवरी, 2013 को गांधी सभागार, लखनऊ में दलित-पिछड़ा-अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन पारख महासंघ द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन को अन्य वरिष्ठ वक्ताओं के अलावा अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ0 उदित राज जी, सम्बोधित करेगें। आप सभी से आग्रह कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर सम्मेलन को सफल बनाएं।

कौशल किशोर
पूर्व श्रममंत्री,
रा. अध्यक्ष,पा. महासंघ
9415005536

पदोन्नति एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए 6 अप्रैल को लखनऊ में विशाल रैली

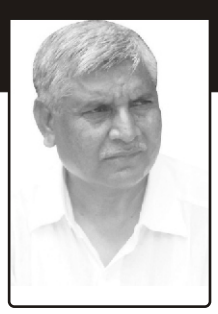

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, पारख महासंघ व अन्य के नेतृत्व में पदोन्नति एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए 6 अप्रैल, 2013 को लखनऊ में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है अपने अधिकारों को सुरक्षित कराने हेतु साथियों सहित पहुंचकर रैली को सफल बनाएं।

पी.सी. कुरील
राष्ट्रीय संयोजक,
रा. भागीदारी आन्दोलन
9415024510

भवन नाथ पासवान
प्रदेश अध्यक्ष
अजा/जजा परिसंघ
9415158866

मुलायम को 'बहुजन' से बाहर करो

डॉ. उदित राज

सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध ने 'बहुजन सुखाय – बहुजन हिताय' की बात कही थी। यह भारत के समाज की सच्चाई भी है। हजारों वर्षों से बहुसंख्यकों का शोषण न केवल जातीय आधार पर हुआ, बल्कि आर्थिक एवं प्रशासनिक आधार पर भी होता रहा। 19वीं सदी तक इसका विरोध व्यापक स्तर पर तो नहीं हुआ लेकिन 20वीं सदी में परिस्थितियां बदल गयीं। दक्षिण भारत में पेरियार एवं नारायण गुरू जैसे लोगों ने ब्राह्मणवाद का पैर उखाड़ने का काम किया तो मध्य भारत में ज्योतिबाफुले एवं डॉ0 अम्बेडकर ने। उत्तरी भारत में सूफी संतों का आंदोलन तो चला परन्तु बहुत असर नहीं छोड़ पाया। कांशीराम जी ने 15 और 85 का नारा दिया और उससे बहुजन शब्द विख्यात हुआ। दलितों ने पिछड़ों को अपना समझकर बहुजन का हिस्सा माना। अगर ऐसा न होता तो जिस तरह से काका कलेलकर की रिपोर्ट दफन हो गयी, वही हश्र मण्डल कमीशन की सिफारिश का भी होता। कांशीराम जी के नेतृत्व में बामसेफ ने मंडल लागू करने की लड़ाई लड़ी। 1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री, वी.पी. सिंह को देवी लाल के जनता दल को छोड़ने से खतरा लगा तो उन्होंने मंडल कमीशन लागू करने का आदेश जारी कर दिया। यदि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का आंदोलन कांशीराम जी ने न किया होता तो वी.पी. सिंह जी नहीं लागू कर सकते थे। इससे पिछड़ों को 27 प्रतिशत का आरक्षण मिला और यह सवर्णों को बर्दाश्त नहीं हुआ। जगह–जगह पर इसका विरोध हुआ और बहुत स्थानों पर उन्हीं पिछड़ों ने इसका विरोध किया जिन्हें इसका लाभ होना था। इसके विरोध में पहला व्यक्ति आत्मदाह करने वाला पिछड़े वर्ग का ही था। यदि पिछड़ों को आरक्षण न मिला होता तो दलितों के आरक्षण पर कुठाराघात नहीं होता क्योंकि अनुसूचित जाति एवं जन जाति का आरक्षण 22.5 प्रतिशत था और उसे आधा–अधूरा लागू करके शेष सरकारी नौकरियां सवर्ण समाज हजम कर जाते थे। अनुसूचित जाति के लोगों ने यदि पिछड़ों को आरक्षण दिलाने की लड़ाई लड़ी तो कोई गलत नहीं किया, क्योंकि यह सामाजिक न्याय की बात थी। इसी की वजह से सरकारी नौकरियों को समाप्त करने का रास्ता निजीकरण एवं उदारीकरण बनाया गया। इसी सामाजिक न्याय की लड़ाई के प्रतिफल मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव एवं राम विलास पासवान आदि तमाम नेता हुए। हालांकि उस समय भी मुलायम सिंह का रवैया मण्डल विरोधी था और जातीय समर्थन के आधार पर उनकी राजनीति टिकी रही लेकिन मंडल का भी पूरा लाभ इनको मिला।

बहुजन समाज का तात्पर्य यह है कि जो शोषित–वंचित हैं और जिस परिस्थिति की वजह से शोषितों की कतार में खड़े हैं, उन्हें बहुजन समाज का हिस्सा नहीं मानना चाहिए। जितना पदोन्नति में आरक्षण का विरोध मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में हुआ उतना सवर्ण समाज के द्वारा भी नहीं किया गया। अब मजबूरी हो गयी है कि मुलायम सिंह जी की स्वार्थी राजनीति का भंडाभोड़ किया जाए। उन्होंने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से 52 प्रतिशत पिछड़ों का लाभ लिया, लेकिन फायदा अपने कुनबे एवं जाति को ही पहुंचाया। डॉ0 जफर महमूद प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने के लिए ओ. एस.डी. नियुक्त किए गए थे और उन्होंने जब 2006 में उ0प्र0 सरकार से पुलिस भर्ती में किन वर्गों एवं जातियों की संख्या क्या थी, आंकड़े जुटाए तो पता लगा कि 82 प्रतिशत तक यादव बिरादरी के ही लोग भर्ती किए गए थे। इस तरह से सबसे ज्यादा

हानि मंडल में शामिल मुस्लिम समाज एवं अन्य पिछड़ी जातियों का हुआ। इतना नुकसान शायद सवर्ण समाज भी न पहुंचाया होगा। अब समय आ गया है कि पिछड़ा मुसलमान मंडल से अपना हिस्सा अलग करने की मांग करे। इसकी शुरुआत उ0प्र0 की सपा सरकार को ही करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए 18 प्रतिशत के आरक्षण की मांग की है। मंशा यह है कि इसे केन्द्र सरकार के पाले में डाल दिया जाए जबकि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने साफ–साफ लिखा है कि मंडल में से मुसलमानों का हिस्सा राज्य सरकार अलग कर सकती है और उसमें संविधान संशोधन या केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं चाहिए। बेहतर होगा कि उ0प्र0 की सपा सरकार ही इसकी शुरुआत करे।

आगामी 28 फरवरी को लखनऊ में कौशल किशोर के नेतृत्व में अति पिछड़ा, मुस्लिम एवं दलित सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें यह मांग उठायी जाएगी कि मंडल में से जितना यादव बिरादरी का आरक्षण बनता है, आबादी के अनुपात में उसे अलग कर दिया जाए। ऐसी मांग करने के लिए समाजवादी पार्टी ने हमें मजबूर कर दिया है। इस आंदोलन में अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ एवं इंडियन जस्टिस पार्टी दोनों ने बढ़–चढ़कर भाग लेने का फैसला किया है। यादव समाज के लोगों को अभी भी मौका है कि वे मुलायम सिंह जी के ऊपर दबाव बनाएं और कहें कि अपने कुनबे को राजनैतिक फायदा पहुंचाने के लिए दीर्घकालीन यादव समाज की क्षति न करें। यादव जाति को छोड़कर उ0प्र0 की दूसरी पिछड़ी जातियों को 28 फरवरी, 2013 के सम्मेलन में भाग लेना चाहिए। दीर्घकालीन लाभ एवं बहुजन एकता के लिए यादव समाज को भी इसको समर्थन करना चाहिए।

हजारों वर्षों की जातीय भावना किसी एक मुद्दे पर नहीं टूट सकती, जो मुलायम सिंह जी सोच रहे हैं। भले ही वे दलितों के आरक्षण का विरोध करें, इस लालच में कि इससे उनको सवर्णों का वोट मिल जाएगा, वह संभव नहीं है। जैसे ही वे मुसलमानों के लिए 18 प्रतिशत के आरक्षण की मांग करेगें, उससे सवर्ण इनसे दूर भाग जाएगा और अंत में नतीजा यह होगा कि दलित, अतिपिछड़े, मुस्लिम एवं सवर्ण सभी इनके विरोधी हो सकते हैं बशर्ते इस आंदोलन को ठीक से चलाया जाए। अब समय बदल गया है, इसलिए दलितों पर उत्पीड़न के लिए ब्राह्मणों एवं राजपूतों को ही नहीं दोषी ठहराया जाना चाहिए, बल्कि पिछड़ों में से कुछ दबंग जातियां न केवल अत्याचार करने में आगे बढ़ गयी हैं, बल्कि राजनैतिक एवं आर्थिक ताक़त सवर्णों से भी ज्यादा अधिकृत कर लिया है। हम एक देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाएं या कितनी भी तकनीक एवं प्रगतिशील विचारों का आविर्भाव हो जाए फिर भी हम जातीय भावना से ग्रसित ही रहेगें। मुलायम सिंह जी को शायद इस सच्चाई का आभास नहीं है कि सवर्ण जाति उनके साथ बहुत दूर तक नहीं चलने वाली है। हां, यह संभव है कि कुछ दिनों के लिए उनका साथ दे लेकिन अंततः बहुजन एकता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और सामाजिक न्याय की लड़ाई पीछे ढकेल दी जाएगी। सभी वर्गों को उनका हक मिले। पदोन्नति में आरक्षण इसी प्रक्रिया की एक कड़ी है, यदि इसके खिलाफ कोई खड़ा होता है तो वह देश की तरक्की में बाधक है।

इंडियन जस्टिस पार्टी, राजस्थान के नवनियुक्त पदाधिकारी

श्री लक्ष्मण सिंह सिंगारिया : प्रदेश महासचिव
श्री पदमाराम गौंसाईं : प्रदेश कोषाध्यक्ष
श्री संजय चौहान : चीफ कोर्डिनेटर, जोधपुर संभाग, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ

राजस्थान में इंडियन जस्टिस पार्टी को गति देने के उद्देश्य से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ0 उदित राज ने श्री लक्ष्मण सिंह सिंगारिया, निवासी – नेहरू कॉलोनी, पांच बत्ती, जोधपुर, राजस्थान – 342001, मोबाइल – 09829520414 को प्रदेश महासचिव, श्री पदमाराम गौंसाई, निवासी–साचोर रोड़, गौंसाई भवन, गांव्पोस्ट – धोरीमाना, तहसील–गुरामालने, जिला–बाड़मेर, राजस्थान – 344704, मोबाइल – 09414529132 को प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं श्री संजय चौहान, निवासी–'सावित्री सदन', जसवंत कैंपस, जोधपुर, राजस्थान, मोबाइल–09829024792 को पार्टी के अंतर्गत गठित पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जोधपुर संभाग का चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है।

उपरोक्त पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 उदित राज को विश्वास दिलाया है कि शीघ्र ही राजस्थान में पार्टी की गतिविधियां तेज की जाएंगी और बूथ स्तर तक की इकाइयों को गठित किया जाएगा।

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए
एक वर्ष : 150 रुपए

विपक्षी एकता को धक्का

अतुल कुमार रंजन

नई दिल्ली। कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही नीतियों के विरोध के लिए विपक्षी एकता के प्रयासों को तब प्रारंभिक धक्का लगा जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, जो इन प्रयासों की धुरी थे, 8 जनवरी की मीटिंग में नहीं आए बावजूद इस बात के कि मीटिंग के लिए निमंत्राण पत्र उन्हीं की ओर से गए थे। यह मीटिंग स्व0 मधु लिमये की स्मृति में बुलाई गई थी किंतु उत्तर प्रदेश विधान सभा की 125वीं वर्षगांठ के कारण जिसमें राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी आने वाले थे, मुलायम सिंह को इस मीटिंग से अनुपस्थित रहना पड़ा ।

स्मरणीय है कि विपक्षी दलों की एकता के लिए पहली मीटिंग 27 अक्टूबर, 2012 को डा0 लोहिया की लोकसभा बहसों के संकलन 'लोक सभा में लोहिया' के लोकार्पण के अवसर पर हुई थी जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, भाकपा के महासचिव सुधाकर रेड्डी, भाकपा के वरिष्ठ नेता एबी बर्धन, फारवर्ड ब्लाक के अध्यक्ष देवव्रत बिश्वास, आरएसपी के अध्यक्ष अबनी रॉय, जनता दल (एकीकृत) के अध्यक्ष शरद यादव, तेलुगु देशम पार्टी के नेता नामा नागेश्वर राव, असम गण परिषद के प्रतिनिधि जोसेफ टोपो, इंडियन जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष डा0 उदित राज, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रघु ठाकुर शामिल हुए थे। इस मीटिंग मे श्री एबी बर्धन के नेतृत्व में समन्वय समिति बनाने का निर्णय हुआ था। इस मीटिंग इसी प्रयास का अगला कदम था ।

इस मीटिंग में 150 से अधिक लोग उपस्थित थे, श्री शरद यादव, अध्यक्ष जनता दल (एकी0) की अध्यक्षता में हुई और इसे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने भी संबोधित किया। राजनेताओं में प्रमुख थे: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अतुल कुमार अंजान, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रघु ठाकुर, कु. दानिश अली, जेडीएस, इंडियन जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष डा0 उदित राज। वरिष्ठ समाजवादी नेता राजकुमार जैन, सत्य प्रकाश मालवीय, डा0 भगवान सिंह, राम गोपाल सिसोदिया, विजय प्रताप, थंपन थामस (उपाध्यक्ष हिंद मजदूर सभा) तथा मस्तराम कपूर ने भी अपने विचार रखे। मीटिंग में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि गैरकांग्रेस–गैरभाजपा राजनैतिक दलों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय समाजवादी लोकतांत्रिक शक्तियों का मंच स्थापित किया जाए जो संबंधित दलों तथा जनांदोलनों से बातचीत चलाए। राजनैतिक विकल्प के प्रस्तावित एजेंडे में जो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं उनमें प्रमुख है: खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का विरोध, बिजली, पानी, ईंधन, जरूरी खाद्य वस्तुओं के निजीकरण पर रोक, खेती और खाद्य आपुर्ति की भूमि के अधिग्रहण पर रोक, जीडीपी आधारित विकास के स्थान पर रोजगोर आधारित विकास, बड़े पैमाने पर आबादी के विस्थापन और पर्यावरण का विनाश करने वाली योजनाओं पर रोक, चुनाव प्रणाली में सुधार जिससे काले धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव समाप्त हो, भ्रष्टाचार और स्त्रियों, दलितों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचारों की रोक–थाम के लिए मजबूत व्यवस्था, सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता और शासन के काम–काज में भारतीय भाषाओं का प्रयोग आदि शामिल हैं ।

सभा इस बात पर एकमत थी कि विकल्प के निर्माण के लिए पूरी शक्ति से प्रयास ही स्व0 मधुलिमये के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभा में प्रस्ताव पास किया गया जिस में राष्ट्रीय समाजवादी लोकतांत्रिक शक्तियों की एकजुटता के लिए मंच स्थापित करने का प्रावधान था।

प्रस्ताव

स्व0 मधुलिमये की पुण्य स्मृति पर 8 जनवरी, 2013 को कांस्टीच्यूशन क्लब, विट्ठलभाई पटेल हाउस, नई दिल्ली में आयोजित यह सभा निश्चय करती है कि :

1. 'लोक सभा में लोहिया' के लोकार्पण के अवसर पर 27 अक्तूबर, 2012 की सभा की भावना के अनुसार राष्ट्रीय समाजवादी लोकतांत्रिक शक्तियों की एकजुटता के प्रयास जारी रखे जाएं और वरिष्ठ वामपंथी नेता श्री ए.बी. बर्धन की अध्यक्षता में समन्वय समिति तत्काल काम शुरू करे ।

2. समन्वय समिति सभी राष्ट्रीय समाजवादी लोकतांत्रिक शक्तियों से विचार–विमर्श कर संयुक्त राजनैतिक हस्तक्षेप के लिए राष्ट्रीय समाजवादी लोकतांत्रिक मंच की स्थापना करे।

3. यह मंच चंडाल चौकड़ी पूंजीवाद (क्रोनी कैपिटलिज्म) और सम्प्रदायवाद की शक्तियों को परास्त करने के लिए वैकल्पिक एजेंडे के आधार पर आगामी लोक सभा चुनाव में हस्तक्षेप करे।

4. मंच इस बात का भी प्रयास करे कि इस समय जो अनेक जनांदोलन (जो लोहिया के शब्दों में एक साथ अनेक क्रांतियां) स्त्रियों, दलितों, आदिवासियों तथा अन्य कमजोर तबकों पर हो रहे अत्याचारों के विरूद्ध और भ्रष्टाचार एवं मानव अधिकारों के हनन के विरूद्ध चल रहे हैं, उनका सहयोग भी प्राप्त किया जाए।

5. सभा का विचार है कि असंतोष, आक्रोश और हताशा के वर्तमान दौर में गैरभाजपा और गैरकांग्रेस के विकल्प की नीति में आगे बढ़ने के लिए काम करते जाने का रास्ता ही सही रास्ता है और हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए ।

आरक्षण का अर्थ है–समाज को आगे लाना'

गत् 5 जनवरी को अनुसूचित जाति, जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के तत्वावद्यान में पाली में संभाग स्तरीय दलित सहित सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि आरक्षण के लिए जागरूक होना आवश्यक है।

अनुसूचित जाति जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. उदितराज ने कहा कि ऐसे कर्मचारी व अधिकारी जो आरक्षण का लाभ लेकर अपने वेतन का कुछ अंश दलितों के उत्थान में खर्च नहीं करते, वे गद्दार हैं। आरक्षण का अर्थ है–समाज को आगे लाना। जो अधिकारी या कर्मचारी आरक्षण के हिसाब से नौकरी में आए हैं उनका नैतिक फर्ज बनता है कि वे अपने समाज के गरीब लोगों को ऊंचा उठाए, यदि वे वेतन का पूरा पैसा अपने व अपने परिवार पर खर्च करते हैं तो उनका आरक्षण का लाभ लेना व्यर्थ है।

उदित राज ने आगे कहा कि राजनीतिक पार्टियों ने कितने ही सालों से दलित वर्गों का शोषण किया, किसी भी पार्टी ने दलितों के हित में नहीं सोचा। वर्तमान में दलित वर्ग की आबादी अधिक होने के बावजूद राजनीति पार्टियां शोषण कर रही है। देश में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। इसके लिए सभी को एक होकर जागरूक होना आवश्यक है।

दौसा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि एससीएसटी व पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनके हक के लिए आगे आने की आवश्यकता है, जब सभी वर्ग के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक अत्याचार होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी जाति हमारे साथ अत्याचार करें तो उसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एससीएसटी वर्ग के साथ भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने कितने सालों तक अन्याय किया, किसी ने उनको ऊंचा उठाने की बात नहीं सोची। अब जागने का समय आ गया है इसलिए सभी को जागरूक होना होगा। परिसंघ की राष्ट्रीय सलाहकार जूथिका बनर्जी ने कहा कि राज्य में इतने साल तक कांग्रेस और भाजपा दोनों पाटियों के नेताओं ने दलित वर्ग के उत्थान के बारे में नहीं सोचा अब इसके लिए दलित वर्ग को जागरूक होना होगा और तीसरे मोंचे के रूप में किरोड़ी को समर्थन देना होगा। कार्यक्रम में दलित एवं आदिवासी विकास परिषद के प्रदेशाध्यक्ष लालचंद हटेला, ज्योतिबा फूले संस्थान के लक्ष्मण गहलोत, राजस्थान आंबेडकर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजू विश्नोई, वन्य जीव संस्थान के अध्यक्ष मिश्रीलाल मीणा, ब्रहमदत्त सरवटे, उप संयोजक एनके राजा, सोहनलाल सिंगाड़िया व लक्ष्मण सिंगाड़िया आदि ने संबोधित किया। संयोजक नवाराम मीणा ने आरक्षण की मांग को लेकर समाज को जागृत होने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन महासचिव सोहनलाल भाटी ने किया। कार्यक्रम में परिसंघ के जिलाध्यक्ष मोहनलाल रासू, बादरलाल झाला, जयसिंह डांगी, बीएल भाटी, पदमाराम गोसाई, विशराम मीणा, ओपी जयपाल, मुकेश मीणा, देवेंद्र मीणा, प्रेमराज, कपूराराम पारंगी, गजाराम समेत पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर आदि जिलों से कई लोग मौजूद रहे।

आह्वान

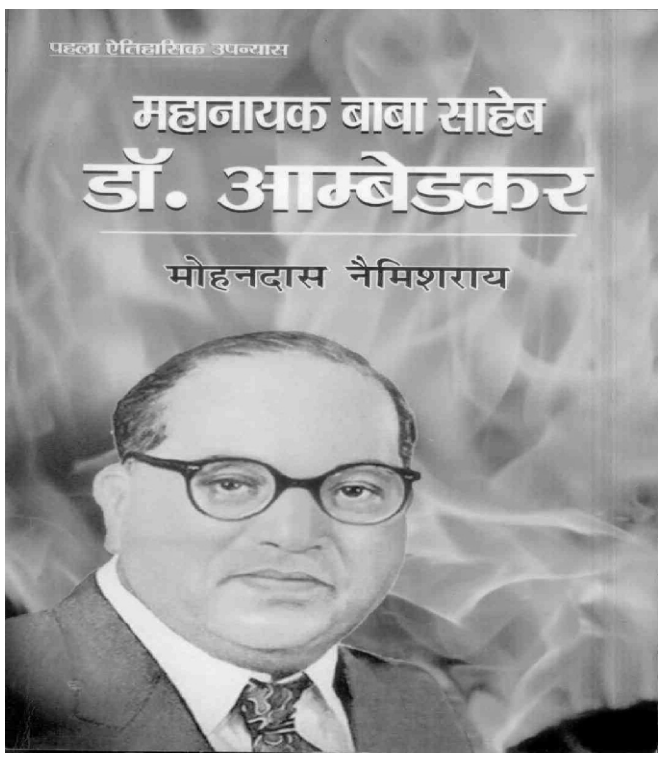

हर सामाजिक कार्यकर्ता को वरिष्ठ लेखक तथा पत्रकार मोहनदास नैमिशराय द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास महानायक बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर अवश्य पढ़ना चाहिए। यह पुस्तक बाबा साहेब डॉ. आम्बेडकर के संपूर्ण जीवन संघर्ष तथा ऐतिहासिक/राजनैतिक/सामाजिक/शैक्षिक घटनाओं पर आधारित तथ्यपरक और दलित अस्मिता से जुड़ा किसी भी भाषा में यह पहला उपन्यास है। यह केवल तीन माह में तीन संस्करण में प्रकाशित हो चुका है। इसमें कुल पृष्ठ संख्या–304 है और मूल्य केवल 80 रूपए। इस पुस्तक को निम्नलिखित स्थान से भी प्राप्त किया जा सकता है– पता–टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन–011–23354841–42।

सूचनार्थ

भारतीय कारपोरेट बोर्डों में विविधता का नितांत अभाव

भारतीय कारपोरेट बोर्ड सदस्यों का जातिगत विश्लेषण(2010)

जाति	संख्या	कुल का प्रतिशत
1. अगड़ी जातियां जिनमें से	8,387	92.6%
(क) ब्राह्मण	4,037	44.6%
(ख) वैश्य	4,167	46%
(ग) क्षत्रिय	43	0.5%
(घ) अन्य #	137	1.5%
2. अन्य पिछड़ी जातियां	346	3.8%
3. अनु. जाति/अनु. जनजाति	319	3.4%

संदर्भ ऊंची जाति (सीरियन क्रिश्चियन के जैसे)

भारत की 1000 शीर्ष निजी व सार्वजनिक कंपनियों के संचालक मंडलों के सदस्यों का सर्वेक्षण–ये कंपनियां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के मार्केट कैपिटीलाईजेशन में 80 प्रतिशत की हिस्सेदार है। संचालक मंडलों की औसत सदस्य संख्या 9 है जिनमें से 88 प्रतिशत इन्साईडर हैं और 12 प्रतिशत स्वतंत्र संचालक हैं। भारतीय संचालकों में से 92 प्रतिशत अगड़ी जातियों से हैं, 3.8 प्रतिशत ओबीसी हैं व 3.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं।

जातिगत विभिन्नता (बीएलएयू) सूचकांक (2010)

औसत	0.12
मध्यिका	0.00
अधिकतम	1.00
न्यूनतम	0.00
मानक विचलन	0.19
वैषमय	1.16
कुरटोटिस	-0.28

यह नमूने पर आधारित विभिन्नता सूचकांक है। कारपोरेट बोर्ड सदस्यों की जातियों पर आधारित बीएलएयू विभिन्न्ता सूचकांक का मध्यिका 0 है अर्थात् कोई विविधता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि सभी कारपोरेट संचालक किसी एक जाति समूह से है।

भारतीयता कारपोरेट बोर्ड (2010)

बीएलएयू	आवृति	कुल का प्रतिशत
0	697	69.7
0.1-0.25	56	5.6
0.26-0.50	246	24.7
>0.51	1	0.0
कुल	1,000	100

यह बताता है कि भारतीय कारपोरेट के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से का बीएलएयू जाति सूचकांक शून्य है अर्थात् कोई विभिन्नता नहीं है... केवल एक कंपनी का बीएलएयू सूचकांक है।

महिलाएं और नेतृत्व

(उन कंपनियों का प्रतिशत जिन्होंने नेतृत्व विकास कार्यक्रम लागू किए हैं)

	भारत में मुख्यालय (प्रतिशत में)	भारत में मुख्यालय भारत में सहायक कंपनी–यूरोप या उत्तरी अमेरिका में मुख्यालय(प्रतिशत में)
लक्षित नेतृत्व विकास कार्यक्रम	17	51
सामान्य नेतृत्व विकास कार्यक्रम	95	95
सामान्य नेतृत्व विकास कार्यक्रम के उपयोग पर नजर	22	59

केटेलिस्ट 2010 इंडिया बैंचमार्किंग रिपोर्ट, सर्वेक्षण में शामिल कंपनियों को दो हिस्सों में बांटती है। भारत में मुख्यालय वाली कंपनियां व यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मुख्यालय वाली कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियां। भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बराबर आने के लिए बहुत कुछ करना होगा। उदाहरणार्थ, घरेलू कंपनियों में से केवल 37 प्रतिशत में महिलाओं के लिए विशिष्ट करियर एडवांसमेंट रणनीति है। इनमें शामिल हैं काम कर रही महिलाओं के संबंध में सर्वेक्षण, उनसे फीडबैक प्राप्त करना व महिलाओं को भर्ती करने और उन्हें कंपनी में बनाए रखने की कोशिश।

अपनी कथा आप कहते आंकड़े

68 प्रतिशत–महिलाओं को आगे बढ़ने की रणनीति वाले कारपोरेट समूह।
75 प्रतिशत– कंपनियां जिन्होंने औपचारिक रूप से लचीली कार्यनीतियां अपनाई हैं।
50 प्रतिशत– कंपनियां जिनके लैंगिक उद्देश्य व लक्ष्य हैं।
60 प्रतिशत– कंपनियां जिनमें विविधता लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रबंधकों की जवाबदेही है।
34 प्रतिशत– कंपनियां जिनमें पुरूषों को लैंगिक जागृति प्रशिक्षण दिया जाता है।
37 प्रतिशत– महिलाओं को आगे बढ़ाने की रणनीति वाले कारपोरेट समूह।

भारतीय कारपोरेट जगत में विभिन्न उद्योगों में जातिगत विभिन्नता (2010)

जिन उद्योगों में न्यूनतम (0.10) विविधता है उनमें शामिल हैं धातु उद्योग, लोहे व स्टील उत्पाद, रबड़ व प्लास्टिक उत्पाद, प्राकृतिक गैस का परिवहन व निर्माण सामग्री। व्यापारिक एवं सेवा क्षेत्र की कंपनियों में निर्माण क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में कम विभिन्नता है। बैंकिंग के क्षेत्र में जाति का बीएलएयू सूचकांक बहुत कम है।

शेष पृष्ठ । का...

भारत बनाम इंडिया

संचार की दुनिया में बड़ी क्रांति आयी है, जिसकी वजह से स्वतः महिलाओं ने अपने तरह से बराबरी और रहन–सहन के तरीके अपनाए। जींस एवं शर्ट भी पहन लिया। उच्च शिक्षा में भी भागीदारी ली। राजनैतिक नेतृत्व भी इनके हाथ में आया। टेलीफोन, मोबाइल एवं तमाम आधुनिक वस्तुओं का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया और बाहर से दिखीं कि अब ये पुरुष के समान पहुंच रही हैं लेकिन सोच के स्तर पर बदलाव बहुत कम हुआ। ये औरतें भी उन्हीं कर्मकांडों एवं मान्यताओं को अपनाया जिससे पुरुष के मुकाबले में कमतर तो होना ही है। पति को परमेश्वर मानना और उसकी दीर्घायु के लिए करवाचौथ का व्रत रखना, क्या पुरुष ने भी महिलाओं के लिए ऐसी भावनाएं दिखायी? क्या इन महिलाओं ने उपरोक्त में धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर किये गए अतीत के भेदभाव का बहिष्कार किया? मर्जी या गैरमर्जी से यदि यदि इनका सेक्स संबंध हुआ और वह गैरकानूनी है तो इन्होंने पूरी इज्जत ही खो दी, जैसे कि सारी इज्जत इनकी इसी में हो और बुद्धि, शिक्षा, ईमानदारी, वफादारी आदि का नंबर शून्य। बलात्कारी से ज्यादा पीड़ा तो जीवनभर समाज एवं मीडिया देते हैं, जब वे कहते हैं कि उसकी इज्जत तार–तार हो गयी और वह चरित्रहीन है। यदि हम अपने समाज को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो दोष दूसरों को देने के बजाय अपनी सभ्यता की कमियों को दूर करना पड़ेगा। सख्त कानून भी समाज को विकृत होने से रोक नहीं पाएगा।

यह कहना बिल्कुल गलत है है कि गड़बड़ी इंडिया में हो रही है भारत में नहीं। जोधपुर में दो गांव ऐसे हैं, जहां 100 वर्ष के बाद बारात आयी, क्योंकि लड़कियां पैदा होते ही मार दी जाती थी। जिस भारत को मोहन भागवत जी आदर्श मान रहे हैं और इंडिया को विकृत, वे दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों की पीड़ा को नहीं जानते। राजस्थान में तमाम ऐसे गांव हैं, जहां पर दबंग कमजोर वर्ग की औरतों के साथ जबरन सेक्स करते हैं लेकिन बात बाहर इसलिए नहीं आती क्योंकि एक तो वहां पर इलैक्ट्रानिक चैनल की पहुंच नहीं है और दूसरा ऐसे तो पहले से ही चला आ रहा है। इंडिया की औरतों को कई गुना ज्यादा मान–सम्मान, भागीदारी, बराबरी मिल चुकी है, जबकि भारत की नहीं।

THE POONA PACT

And What Went Before It

Vishal Mangalwadi

On the 80th anniversary of the infamous Poona Pact, we are Publishing an edited excerpt from Vishal Managalvadi's India: The Grand Experiment that sheds light on the role played by the British rulers, Indian nationalist elites and leaders of India's "Depressed Classes" in paving -and blocking- the road to social and political emancipation of the Indian masses.- EDITORS

Many upper-caste Indians believe that the Dalits in India were liberated by the Indian National Congress and Mahatma Gandhi. The fact is that the Congress 'involvement with the plight of the oppressed began only in 1917, and from the beginning Congress' integrity was doubtful. A sketch of that history is enlightening.

On 20 August 1917, during the First World War, the then Secretary of State for India, Edwin Montagu, made a formal announcement on behalf of the British Government. He declared that his government's post-war intention for India was to develop "self goerning institutions with a view to progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire." The announcement was understood to mean that India would be given the kind of autonomy already enjoyed by Canada, Australia and New Zealand.

Indian politicians had been expecting this kind of a declaration and were preparing schemes for changes in the constitutional structure of India that would suit their interests. Two of the schemes that had attracted special attention during 1916-1918 were "the Congress-League scheme" which was based on presidential theory of government and the "Montatagu-Chelmsford Plan" which relied on the parliamentary theory of government.

The Congress needed the endorsement of the lower castes to be able to push forward its scheme as the "national demand". Its problem was that although the Muslim league had approved its proposal, the "depressed classes" did not trust the upper caste leadership of the Congress. In 1895, some Congress leaders had been willing to allow the leaders of the Social Conference to use its platform to oppose the enslavement of the Indians by the Hindu Social order. The idea was dropped when Mr. Tilak's followers threatened to burn down the Congress pandal if anyone dared to oppose Hindu customs from that platform. The "untouchables" retaliated by protesting against the Congress and by burning its effigy. Understandably, their antipathy against the Congress had continued till 1917 when the Congress needed their support.

That distrust made it difficult for the Congress to obtain the endorsement of the backward classes for the Congress- League scheme. Instead of apologizing for its earlier timidity and indifference, the Congress tried deception to obtain Dalit endorsement for its scheme. It wrote a resolutiion of its own and used a highly respected figure-Sir Narayan Chandavarkar, the President of the Depressed Classes Mission Society- to get it passed along with other resolutions in a meeting held on 11 November 1917, in Bombay. The highlights of the key resolutions read as follows:

First Resolution affirmed "Loyalty to British Government" and prayed for victory to the Allies in the First World War then going on.

Second Resolution carried at the meeting by an overwhelming majority, the "dissentients being about a dozen," expressed approval for the scheme of reform in the administration of India recommended by the Indian National Congress and the All India Muslim League.

Third Resolution carried unanimously said: "... this public meeting of the Depressed Classes strongly feels that in the scheme of reform and reconstitution of the Legislative Councils which Government may be pleased to adopt, due regard be paid to the interests of the said classes. This meeting therefore prays the British Government to be so gracious as to protect those interests by granting to those classes the right to elect their own representatives to the said Councils in proportion to their numbers."

Fourth Resolution unanimously carried at the meetings was: "That the Government be prayed for the adoption... of a compulsory and free system of education..."

Fifth Resolution also carried unanimously read: "That the Chairman of this public meeting be authorised to request the Indian National Congress to pass at its forthcoming session a distinct and independent resolution declaring to the people of India at large the necessity, justice and righteousness of removing all the disabilities imposed by religion and custom upon the Depressed Classes... These disabilities, social in origining, amount in law and practice to political mission and propaganda of the Indian National Congress."

Sixth Resolution Prays all Hindus... of the higher castes, who claim political rights, to take steps for the purpose of removing the blot of degradation from the Depressed Classes..."

The Indian National Congress followed up the above-mentioned meeting with its own meeting and passed the following high-sounding resolution:

"This Congress urges upon the people of India the necessity, justice and righteousness of removing all disabilities imposed by custom upon the Depressed Classes, the disabilities being of a most vexatious and oppressive character, subjecting those classes to considerable hardship and inconvenience."

A few years later, Dr. Bhimrao Ambedkar called the above resolution a "strange event". The Congress had functioned for 32 years, it had championed the cause of India's political independence, it had campaigned against the British Raj, but it had never spoken up for the freedom of the lower castes. Now, only when it needed their political support, it found itself speaking up for them- but only to get their vote. Mr. Kanshi Ram, the President of the Bahujan Samaj Party (BSP), and Dr. Ambedkar's de facto successor, described this "deceptive" appeal for justice "mischievous"...Later events showed that the Congress had no intention of doing anything about the oppressiveness of Hindu society. Nevertheless, the resolution had compelled Congress to admit that the internal atrocities of the Indian society had to be dealt with, as well as the immorality of the alien rule.

A few days after the first meeting in Bombay, the dozen "dissentients" organized another meeting of the lower castes, again in Bombay. It was this meeting that shaped the attitude of Dr. Ambekar and Mr. Kanshi Ram towards the upper-caste politicians. Bapuji Namdeo Bagade, a leader of the non-Brahmin party, chaired the meeting. The resolutions passed in this meeting nullified some of the resolutions passed in the first. Following are the key resolutions passed in the second meeting:

1. Resolution of loyalty to the British Throne.

2. That this meeting cannot give its support to the Congress-League scheme in spite of its having been declared to have been passed at the meeting of 11th November 1917 by an overwhelming majority.

3. That it is the sense of this meeting that the administration of India should be largely under the control of the British till all classes and specially the Depressed Classes, rise up to a condition to effectually participate in the administration of the country.

4. That it the British Government have decided to give political concessions to the Indian Public, this meeting prays that Government should grant the Untouchables their own representatives in the various legislative bodies to ensure to them their civil and political rights.

5. That this meeting approves of the objects of the Bahiskrit Bharat Samaj (Depressed India Association) and supports the deputation to be sent on its behalf to Mr. Montagu.

6. That this meeting prays that Government looking to the special needs of the Depressed Classes, should make primary education both free and compulsory. That the meeting also requests the Government to give special facilities by way of scholarships to the students of the Depressed Classes.

7. That the meeting authorises the President to forward the above resolutions to the viceroy and the Government of Bombay.

What this meeting said in effect was that the Dalits would rather remain under the British rule, than gain political independence only to be ruled by the Brahmins. As Dr. Ambedkar was to put it later in his book Annihilation of Caste, "Swarajya (Independence) has got no significance, without establishing a caste-less society". This is because he knew from his experience that "Political brutality is nothing when compared with social brutality."

This sentiment of the lower castes made it imperative for Mahatma Gandhi to work for their "emancipation".

Dr. Ambedkar refuted that claim in his book, What Gandhi and the Congress have done for the Untouchables. He presented the case that even during the struggle for national independence, Mahatma Gandhi and the Congress did all that they could to deceive the lower castes, and to keep them under the control of the upper castes. It is not necessary to restate their case here. An important fact on which the case rests follows:

After Lord Irwin announced in 1929 that the British government would honour the 1917 commitment to give self-rule to India, Round Table Conferences were held in London 1930-32 to settle the modalities of transfer of power. Leaders of the scheduled castes demanded that, given the fact that the upper castes were not concerned for them, they should be allowed to select their own legislators, so that their representatives would represent their point of view.

Mahatma Gandhi opposed the proposal because he feared that such a scheme would reinforce the walls that already separated the upper and lower caste Hindus. His proposal was that certain electorates should be reserved for candidates from the scheduled castes, but that all voters must exercise their franchise to elect the legislator. This way he or she would represent the entire constituency, not just the scheduled castes.

Although Gandhi's proposal sounded good, it had a problem. It meant that the scheduled-caste candidates would fight amongst themselves, but that the candidate backed by the higher castes would always win. So, any scheduled-caste candidate who wanted to win an election and always need to be subservient to the upper-caste voters. The Round Table Conference failed in resolving the issue, and all participants-including Gandhi-agreed that they would leave the matter to be decided by the British Prime Minister, and that his decision would be accepted by all.

The British Government announced its "Communal Award" in favour of Dr. Ambedkar's proposal on 17 August 1932. Gandhi saw fresh dangers in Dr. Ambedkar's Scheme. What if Dr. Ambedkar's Republican Party joined hands with Mr. Jinnah's Muslim League? Together, it would not be difficult for the Muslims and the lower castes to beat the upper-caste Hindus in a battle of numbers. Democracy-the numbers game-would then be to the disadvantage of the upper castes.

Mahatma Gandhi, therefore, went on his longer ever "fast-unto-death" in Poona (Pune). This was not directed against the colonial Raj. Dr. Ambedkar described its purpose in a statement on 19 September 1932.

"*I should have thought that a well-wisher of the Depressed Classes would have fought tooth and nail for securing to them as much political power as might be possible in the new Constitution...He not only does not endeavour to augment the scanty political power which the Depressed Classes have got under the Communal Award, but on the contrary he has staked his very life in order to deprive them of little they have got.*"

National and international pressure was mounted on Dr. Ambedkar to surrender this possibility of freedom and save Gandhi's life. The upper-caste followers of Mahatma Gandhi threatened dire consequences should he die. Dr. Ambedkar's statement confirms:

Whether he knows it or not, the Mahatma's act will result in nothing but terrorism by his followers against Depressed Classes all over the country.. the Mahatma is releasing reactionary and uncontrollable forces, and is fostering the spirit of hatred between the Hindu Community and the Depressed Classes by resorting to this method and thereby widening the existing gulf between the two.

Dr. Ambedkar realized that a large number of the untouchables might be forced to pay with their lives if Mahatma Gandhi died. So to save his life and theirs he surrendered their political power through the "Poona Pact" of 24 September 1932. As a result, during most of the 50 years of Independence the lower castes have had to play second fiddle to the upper caste rulers.

Gandhi succeeded politically, but only in ensuring that the lower castes remain subservient to the upper castes in free India. As Dr. Ambedkar put it, the policy of the "Joint Electorate" which Mahatma Gandhi had enforced by staking his life is,"...from the point of view of the Hindus to use a familiar phrase a 'rotten borough' in which Hindus get the right to nominate an untouchable to sit nominally as a representative of the untouchables but really as a tool of the Hindus."

DRIVE AWAY MULAYAM FROM "BAHUJAN" SAMAJ

Dr. Udit Raj

First of all, it was Lord Buddha who had talked of optimum happiness for maximum number of people. It is also a reality for the Indian society. For thousands of years, majority of the people have been exploited not only on the basis of caste but also on economic and administrative basis. Upto the nineteenth century, there was no widespread opposition to this system but the situation started changing in the twentieth century. Leaders like Periyar and Narain Guru in South India were greatly responsible for uprooting Brahmanism while Jyotibaphule and Dr. Ambedkar made similar efforts in Central India. Sufi saints also started their campaigns in this regard in North India but it could not have much of an impact. Kanshi Ram Ji gave a call of 15 and 85 which gave prominence to the word 'BAHUJAN' . Dalits took backwards as belonging to their own social milieu. Had it not been so, Mandal Commission recommendations would have met the same fate as the Kaka Kalelkar Report. BAMSEF took upon itself the challenge of implementing the Mandal Commission recommendations under the leadership of Kanshi Ram Ji. when the then Prime Minister V.P. Singh came to know that Chaudhary Devi Lal could quit Janata Deal, he issued orders in the year 1990 for the implementation of the recommendations of the Mandal Commission. Had Kanshi Ram Ji not started the campaign for the implementation of the recommendations of the Mandal Commission, V.P. Singh Ji could not have passed orders for its implementation. As a result, backwards got 27% reservation which was not acceptable to the upper caste people and there were widespread protests against this and at many places the same backward people also opposed who were ultimately to gain from this decision. The first person to commit self-immolation against this decision was from a backward community. Had the backward community not got reservation, the reservation quota earmarked for Dalits would not have got a blow because because the reservation quota for SC/ST people was 22.5% and by implementing it half-heartedly, the upper caste people used to swallow a large chunk of their share. If the people belonging to SC community had fought for reservation for the backwards, there was nothing wrong with it and it was in fact it was a matter of social justice. It is because of this that privatization and liberalization were introduced so that Government jobs could be abolished. Leaders like Mulayam Singh Yadav, Lalu Prasad Yadav, Sharad Yadav and Ram Vilas Paswan etc took up the cudgels for this struggle for social justice even though at that time, Mulayam Singh was against Mandal Commission and he took maximum advantage of caste based politics.

Those who are the victim of caste discriminations fall under the ambit of "Bahujan" Samaj but due to changed circumstances, some castes have assumed the role of exploiters so they should be driven out. Thus Mulayam Singh should be driven out of Bahujan Samaj.The opposition to reservation in promotions by the upper caste people pales into insignificance if it is compared to the opposition to reservation in promotions under the leadership of Mulayam Singh Ji. Now the time has come when the selfish politics of Mulayam Singh Ji is exposed. He took advantage of 52% reservation for backwards but people of his own caste and family members were made beneficiaries of the same. Dr. Jafar Mahmood in the Prime Minister's Office was appointed as the Officer on Special Duty for the preparation of the Sachhar Committee Report. When Dr. Jafar Mahmood in the year 2006 asked for the details of recruitment in the police force in Uttar Pradesh for different castes and categories, it was shocking to know that 82% of the people belonged to Yadav community. Thus the maximum damage was done to the Mualim community and other backward clases. So much damage would not have been done even by upper caste people. Now it is high time that the Backward Muslim community should separately demand their share from the Mandal Commission. A beginning in this regard should be made by S.P. Government in Uttar Pradesh but it is the Samajwadi Party which has befooled Muslim community by asking for 18% reservation for them. Their real intention is to put the ball in Centre's court whereas actually the Ranganath Commission had clearly said that Muslims' share from the Mandal Commision can be taken out by the State Government and for this purpose, neither constitutional amendment is required nor any approval of the Central Government. Thus, it would be much better if the U.P. G overnment makes a beginning in this regard.

On 28th February, 2013, a Conference of Backwards, Muslim and Dalits is being held at Lucknow under the leadership of Kaushal Kishore, in which it will be demanded that the share of reservation of Yadav community in the Mandal Commission may be taken out in proportion to their population. The Samajwadi Party has forced us to make such a demand. In this campaign, the All India Confederation of SC/ST Organizations and the Indian Justice Party have resolved to take active part in this campaign. It is high time that people from the Yadav community should exert pressure on Mulayam Singh Ji and appeal to him that he should not harm the interests of the Yadav community as a whole in the long run just for the benefit of the members of his own family. All the other backward caste people except Yadav community should take active part in the Conference to be held at Lucknow on 28.2.2013. For long run gains and for Bahujan unity, Yadav community should also come forward to support our demand.

Caste prejudice which has been prevailing for thousands of years cannot be removed on the basis of just one issue. May be Mulayam Singh Ji is opposed to reservation for Dalits, it is not possible that by adopting this policy, he will be able to win over votes of the upper caste people. As soon as he makes a demand of 18% reservation for Muslims, upper caste people will leave his camp and the result will be that Dalits, Most Backwards, Muslims and upper castes may all become his opponents provided the campaign is carried out on the right path. Now the time has changed and we cannot blame only Rajputs and Brahmins for atrocities against Dalits, but some powerful communities from amongst backward castes are not only committing atrocities against Dalits but have become economically and politically more powerful than upper caste people. We shall continue to be deeply engrossed in caste prejudices despite the fact that we may leave India and start living in a foreign country or howsoever technologically we may become advanced. Mulayam Singh is perhaps not aware of the stark reality that the upper caste will not stand by him in the long run. Yes, it is possible that they may stand by him for a short duration but ultimately it will adversely affect Bahujan unity and the struggle for social justice will get a jolt. All sections of the society should get their due. Reservation in promotion is just one step in that direction and if anybody creates a hurdle in its implementation, that will deemed to be a retrograde step in the development of the country.

... Rest of Page-8

India Vs Bharat

the same time, so many emotional, social and violent disturbances are taking place but there are certain specific issues which are adding fuel to the fire. A lot many efforts are being made at different levels be it Government, NGOs and Human Rights activists for tackling the social and economic problems but a very few people know outside India about the problems of the untouchables (Dalits). The reason is that the victims do not have the voice to air their grievances. Secondly, discrimination is justified under the garb of Hinduism so that the global community is given the impression that it is really a Hindu way of living and thus there is no need to interfere but the situation has now changed so much that not only the victims are resenting but the global community is also taking a keen interest in their welfare. Currently, it would not be an exaggeration that the caste discrimination is being more focused than apartheid. European Parliament has taken up this issue as also the British Parliament and detailed discussion in the houses and resolutions can be easily accessed on net. There was a Congressional hearing of Committee on international relations of the House of Representatives of the U.S. Congress in the Capital Hill, Washington, America in 2005 in which Dr. Udit Raj was also invited and he forcefully pleaded with the American community through Congressmen and Senators to join the struggle to end the caste discrimination on the basis of birth and descent. More than 170 million untouchables live in India. If the issue of discrimination is not resolved, not only the peace in India will be affected but the efforts of global level peace will also be jeopardized.

The Human Rights activists of the world must get attentive to caste discrimination and had it been in the power and capacity of the untouchables to fight it out, such an appeal would not have been necessary. The untouchables are looking for global support. Though there are many human rights organizations and U.N. programmes related to Indian problems but most of them focus on non-issues like human trafficking, aids, drug addiction etc. but they are not that serious as caste discrimination. A few facts regarding their discrimination will throw ample light on the gravity of the situation:

Despite the fact that many Dalits do not report crimes for fear of reprisals by the dominant castes, official police statistics averaged over the past 5 years show that 13 Dalits are murdered every week, 5 Dalits' homes or possessions are burnt every week, 6 Dalits are kidnapped or abducted every week, 3 Dalit women are raped every day, 11 Dalits are beaten every day and a crime is committed against a Dalit every 18 minutes

The Indian Constitution does abolish untouchability under Article 17 but the deep-rooted caste system is still intact though the Government of India never misses an opportunity to rebut the fact at the global level that there is discrimination as far as constitution is concerned but on the ground, things are very different. Dr. Udit Raj and his colleagues have been airing these grievances in Human Rights Council but always, Government of India is denying any discrimination. An American journalist, Robin Jeffry has tried to find out journalists from these communities but was unable to find a single Dalit journalist. Not only, they are excluded from Media but in other areas like IT/Telecom sector, trade and industry, art and culture , film industry and higher education, there is hardly any Dalit. Whatever the respect, dignity and empowerment has come to them, is due to reservation in government jobs and politics. It was the British who considered the demand raised by Saviour of Dalits and Tribals, Dr. Ambedkar. Had the British rule not been there, even these rights would not have come to them. It were the Christian Missionaries who opened the door of education to Dalits for the first time in India. For thousand s of years, no statesman, no hero, no Hindu God ever rescued Dalits from bondage. Establishment of a peace centre or other similar efforts will greatly help in abolishing discrimination against Dalits.

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16 ● Issue 4 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 January, 2013

जहां मन हिंसा से मुड़ता है, वहां दुःख अवश्य ही शांत हो जाता है।

-गौतम बुद्ध

India Vs Bharat

Dr. Udit Raj

RSS Chief Mohan Bhagwat has given a statement that crimes like rape and discrimination against women are happening because of the impact of Western culture. VHP leader Ashok Singhal and other leaders like Asaram Bapu have expressed similar views. Before making such statements, these leaders should have realized that if our people get influenced by the western culture, there must be some shortcomings with our own culture.Europeans and Americans do not complain that their societies are adversely influenced by Hindu culture where it is quite possible that our culture is affecting their life style because a large number of our people live in these countries. Very few Americans and Europeans live in India and soon after completing their business or official assignments, they return to their respective countries and do not become a part of our culture. It would have been better if these leaders had accepted the shortcomings of our own culture.

Our culture is based on caste system and women are as unfortunate victims of this system as Dalits, Tribals and Backwards. For thousands of years, the upper castes are not tired of calling it better than other cultures. Europeans and Americans rarely criticize Indian culture but we do not miss any opportunity to criticize their life- style and values. Muslims are even more critical about the Western way of life. Western culture is frequently attacked by some Muslim leaders at public meetings that in the West, ladies move about half-nude and divorce and abortion rate is very high. I have had an opportunity to visit several western countries but I never came across an opportunity when Indian or Muslim culture was criticized by anyone.

We have two major Epics – one is The Gita and the other is Mahabharata. Sita was the cause of the war between Lord Rama and Ravana. Sita was advised not to cross the Lakshman Rekha but she disobeyed it and Ravan abducted her. This episode also shows women in a poor light. War takes place between the two and after Ravan is defeated, Sita returns to her home and is subjected to undergo a fire test to prove her chastity or honour. Why men do not undergo any such fire test as if they are not accountable . From this, it is quite evident that woman is a consumer item and stands at a lower footing than man. The matter does not end here and the situation becomes much more dreadful when Ram turns out Sita from his house because a neighbour questioned her chastity. The situation becomes much worse when she was left alone in a forest and was denied even the basic minimum right to live separately . Today's law does not allow such an act and in the case of a divorce, the divorced woman is entitled to maintenance allowance from her husband. If our culture and civilization treat women like this , it is but natural that they will be influenced by the Western culture where women have got freedom, respect and self-confidence. So, instead of blaming others, there is a great need to analyse own culture and ensure that the age-old rotten values and traditions which put women on a lower pedestal are discarded. In the past, women were also treated inferior to men in the western society also but they removed such discriminations over a period of time. We need to understand the pace of progress of Greek civilization and how it evolved leaving aside retrograde traditions. Plato, Socretes's pupil, followed his Master's philosophy only to the extent that it looked logical or for the good of the humanity which really helped in the advancement of the Greek culture. Aristotle was very much influenced by the philosophy and principles of Plato but he also followed only those principles which looked rational. Like this, the society was able to break the shackles of old customs and traditions and today's western culture is essentially based on such traditions and customs. Whatever progressive ideas and traditions we talk about but at the end of the day, nearly everybody says that there is nothing to beat the past i.e. the old traditions are always considered the best. No society is more hypocritical than ours in claiming that our religion, way of thinking and way of living is the best. Today, when women want to lead their life according to the rights guaranteed by the constitution , they are blamed to be influenced by the western culture because there is more freedom, human rights, equality and self-dependence in their society. With the growing awareness about equality and self-respect, life-style also changes and this is incidentally in tune with the Western values. The western society has not imposed their life style and values on us. Had we discarded decadent and rotten tradition of our society then there was no need to be influenced by western civilization . Then in that situation we could have also contributed to the cultural values of other societies. Even today the couplet of Ramcharitmanas is there which says that the drum, rogues, shudras, animals and women need to be beaten, has not been openly condemned and boycotted. In simple language, it means that women can be made to work only by beating and they are like animals. That portion of Mahabharat has also not been condemned so far in which Pandavas lose everything in gambling and when nothing is left, they put Draupadi on stake and finally the Kaurvas win her. Is anybody allowed to put his wife on stake in the game of gambling in today's society. The husbands who themselves did not give proper respect to their wife Draupadi and treated her like a consumer item and how Yudhishter was treated as a Dharmaraj while actually the Kaurvas were less to be blamed but it has been projected in such a way that they are the real culprits. In fact, the Kaurvas' claim was more legitimate and even when they had pulled Draupadi's saree , who was to be blamed ?

There has been a revolution in many areas in most of the western countries but this could not happen in our country. Many saints like Kabir did try to change the Indian society but were unsuccessful in doing so. Jyotibaphule became a trendsetter in the area of women's freedom and education but the society could not be transformed. Ambedkar's campaign did challenge caste and rotten tradition of Manuvadi system, but it has still to go a long way. A human being cannot resist being influenced by any source which gives him equality, self-respect, freedom and self-dependence. Had we broken the rotten customs and traditions in time, then these basic requirements could have been achieved through our own system and there would have been no need to be influenced by the western culture. China was no less orthodox than us but there the cultural revolution was brought about by the State. Reactionary forces were crushed with the power of the gun. Had they not brought cultural revolution, then the progressive and humanitarian values of other cultural societies would have influenced their society also. We got Independence about 65 years ago and various Government plans were made but no attempts have been made to break the shackles of the caste system and male chauvinism. This unfinished task was left to whom to complete , none other than those who are male chauvinists but why should they have worked for the transformation of the society. There should have been Government intervention but just to keep their vote-bank intact, most of the social and political leaders remained neutral in changing the society. Whether it is social or political leadership, most of the leaders were themselves had an orthodox approach and had a mindset of the policy of discrimination and inequality.

There has been a big revolution in the field of communication technology due to which women, on their own, have adopted equality, freedom and modern life style. They started wearing jeans and shirts. In the area of higher education also, they have made significant progress. They have made strides in politics. They made use of all the modern gadgets like telephones, mobiles and all other similar things and give the impression that they are now quite equal to men but there was no much change in their mindset. These women continue to adhere to old values and traditions and that makes them inferior role to their menfolk. The women still treat their husbands like gods and keep Karvachauth fast for their long life. Have the men got similar feelings for women? Have these women ever protested against men for their religious and social discrimination in the past? If they go for illegal and forced sex, they lose their character and honour as everything and, as if their intelligence, education, honesty and faithfulness, etc. have no value. Why similar yardsticks are not applicable in case of men? More than the rapist, it is the society and the media which torture the rape victim when they say that she has lost everything and is characterless. If we want a healthy society, then we will have to revolutionize our society instead of blaming others. If this is not done even stricter laws may not protect women .

It is totally incorrect to say that such like incidents are happening in India and not Bharat. There are two villages in Jodhpur where a marriage party came after 100 years, because every girl child was killed soon after birth. Mohan Bhagwar Ji, who considerd Bharat as ideal and India as perverted, is not aware of the atrocities and discriminations suffered by Dalits, Adivasis and Backward women. There are so many villages in Rajashtan where the musclemen forcibly do sex acts with the womenfolk of weaker sections but this fact does not come to light because firstly, the electronic channels cannot reach there and secondly, because it has been accepted practice Women of India have got many-times more freedom, self-respect and equality as compared to the women of Bharat.

The world is undergoing drastic changes and so many material objects have been created for comfortable living of human beings and at

Rest on Page-7...

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

Computer typesetting by N. K. Karn